निर्यात की इजाजत मिलने से चीनी के दाम में मामूली तेजी

एम ग्रेड चीनी का दाम 3100 प्रति क्विंटल से बढ़कर 3150 प्रति क्विंटल हुआ

जयश्री भोसले | पुणे

चीनी के दामों में चल रही सुस्ती कुछ टूटी है। पिछले हफ्ते इसके दाम में 3 पर्सेंट की तेजी आई। शुगर इंडस्ट्री चीनी के दाम पर दबाव की वजह से केंद्र सरकार से इंसेंटिव्स की मांग कर रही थी। इसके बाद सरकार ने इंडस्ट्री को 20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन बिना इंसेंटिव के। इंडस्ट्री को डर है कि इससे बात नहीं बनेगी और आगे चलकर फिर से चीनी के दाम पर दबाव बन सकता है।

शुगर ट्रेड से जुड़े अभिजीत घोरपड़े ने बताया कि एम ग्रेड चीनी का दाम " 3100 प्रति क्विंटल से बढ़कर " 3150 प्रति क्विंटल इसलिए पहुंचा क्योंकि ट्रेडर्स को सरकार से निर्यात पर इंसेंटिव की उम्मीद थी। उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई कीमत पर चीनी की बहुत खरीद-बिक्री नहीं हो रही है। मुंबई के होलसेल मार्केट में थोक विक्रेताओं ने बताया कि निर्यात की खबर आने के बाद चीनी

- शुगर इंडस्ट्री चीनी के दाम पर दबाव की वजह से केंद्र सरकार से इंसेंटिव्स की मांग कर रही थी। इसके बाद सरकार ने इंडस्ट्री को 20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन बिना इंसेंटिव के

के दाम में 25 रुपये क्विंटल का इजाफा हुआ है। वहीं, बॉम्बे शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक जैन ने कहा, 'बिना इंसेंटिव्स के चीनी के निर्यात में दिक्कतें हो सकती हैं।' उधर, ट्रेडर्स का दावा है कि यूं तो गर्मियों के मौसम में चीनी की खपत बढ़ जाती है, लेकिन बंपर प्रॉडक्शन की वजह से बड़े खरीदार इसका स्टॉक तैयार नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्यात के लिए मिल वाइज कोटा तय किया है। यह कदम मिनिमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट कोटा (MIEQ) स्कीम के तहत उठाया गया है। वहीं, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सफेद चीनी के अलग से निर्यात की अनुमति भी दी है। हालांकि, अगर मिलें चीनी का निर्यात करती हैं तो उन्हें "10 प्रति किलो का नुकसान उठाना पड़ेगा। इंडस्ट्री इस नुकसान को कम करने के तरीके तलाश रही है।

नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश नायकनवारे ने कहा, 'सरकार के चीनी के निर्यात की अनुमति देने से इंडस्ट्री को दोहरा फायदा मिलेगा। पहला, इसमें इंडस्ट्री को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन (DFIA) स्कीम का फायदा मिलेगा। साथ ही, निर्यात के चीनी के घरेलू दाम में तेजी आने से उनका मार्जिन बढ़ेगा।' शुगर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सरकार से बहुत वित्तीय मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, इंडस्ट्री इसके लिए राज्य सरकारों के साथ लॉबिंग कर रही है।